हर पहलू की हो जांच

अगर बिना किसी जांच-पड़ताल के, आरंभिक चरण में ही इतने साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनके आधार पर ये दो संभावनाएं पूरी तरह नकारी जा सकती हैं तो स्वाभाविक ही जांच का दायरा सीमित हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ जवानों के मानसिक स्वास्थ्य का मसला नहीं है।

सुमन वर्मा।।

अमृतसर के खासा स्थित बीएसएफ हेडक्वॉर्टर में जिस तरह से एक जवान ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपने चार सहकर्मियों की हत्या की और खुद भी मारा गया, वह चिंतित करने वाला वाकया है। घटना का जो ब्योरा दिया गया है, उसके मुताबिक जवान सीटी सत्तेपा ने पहले ऑफिस पहुंचकर एक क्लर्क को गोली मारी। फिर बैरक जाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसने ऑफिशियेटिंग कमांडेंट के वाहन पर भी गोली चलाई, लेकिन वह बच गए। यह सच है कि अभी आरंभिक सूचनाएं ही सामने आई हैं, जिनके आधार पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला जा सकता। पुलिस ने तो मामला दर्ज किया ही है, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो बातें अभी से साफ कर दी हैं। एक, यह छुट्टियां न मिलने जैसी स्थिति से नाराजगी का मामला नहीं है। दो, इसमें पुरानी रंजिश का भी कोई एंगल नहीं है। अगर बिना किसी जांच-पड़ताल के, आरंभिक चरण में ही इतने साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनके आधार पर ये दो संभावनाएं पूरी तरह नकारी जा सकती हैं तो स्वाभाविक ही जांच का दायरा सीमित हो जाता है। बेहतर होता बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी अपने इस निष्कर्ष को सार्वजनिक करने के बजाय जांच प्रक्रिया को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचने देते और फिर उससे निकले निष्कर्षों पर विचार करते।

यह खास तौर पर इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अपना पक्ष रखने के लिए वह जवान भी अब जीवित नहीं है। ध्यान रहे, यह अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल ही सितंबर की 23 तारीख को दक्षिण त्रिपुरा के गोमती जिले में हुई आपसी तकरार में दो बीएसएफ कर्मी मारे गए थे और एक घायल हो गया था। उससे पहले 2019 में एक बीएसएफ कर्मी ने दो साथियों को घायल करने के बाद अपनी जान ले ली थी। मई 2018 में भी एक बीएसएफ जवान ने तीन साथियों की हत्या कर खुद को शूट कर लिया था। उस घटना के बाद बीएसएफ ने अपने सुरक्षाकर्मियों के लिए सालाना मानसिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दिया था। लेकिन यह सिर्फ जवानों के मानसिक स्वास्थ्य का मसला नहीं है। उनकी वर्किंग कंडिशंस, उनके ड्यूटी आवर्स और उनके साथ होने वाले व्यवहार के सवाल भी इससे जुड़े हैं। इस बारे में कई स्टडी रिपोर्ट्स भी उपलब्ध हैं।

जरूरत यह है कि इन्हें समग्रता में देखा जाए और उनमें जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें मिलाकर एक दिशानिर्देश तैयार किया जाए। उसके बाद इन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने की पहल की जानी चाहिए। उम्मीद है कि इससे खासा जैसे मामलों से भविष्य में बचने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे बीएसएफ जैसे संगठनों में नौकरी के लिए युवाओं का भी आकर्षण बढ़ेगा।

सृष्टि की उत्पत्ति

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।
संतो, महात्माओं व ऋषियों के कथन अनुसार इस शिवलिंग का संबन्ध सृष्टि की उत्पत्ति से है । वैसे इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित काठगढ़ महादेव का मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां दो भागों में बंटा घशिवलिंग हैं। माना जाता है कि मां पार्वती और भगवान शिव के दोनों भागों के बीच का अंतर घटता बढ़ता रहता है। यह अंतर ग्रहों व नक्षत्रों के परिवर्तित होने के अनुसार ही बदलता रहता। विशेषता– सर्दियों में यह दो पाषाण वाला शिवलिंग धीरे धीरे एक हो जाता है और गर्मियों में धीरे धीरे अलग हो जाता है अनुमानित तीन इंच का अन्तर रहता है। यह प्रकृति का नियम सृष्टि के सर्जन से चल रहा है। काठगढ़ शिव मन्दिर का शिवपुराण में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मा व विष्णु भगवान के मध्य बड़प्पन को लेकर युद्ध हुआ था।

संपादकीय

जूनियर पार्टनर रूस

ऐसी कई रिपोर्ट आई हैं, जिनके अनुसार रूस ने चीन से सैन्य और अर्थव्यवस्था को लेकर मदद मांगी है। अगर चीन इसे मान लेता है तो रूस उसका जूनियर पार्टनर बन जाएगा। चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ती जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भारत की रक्षा क्षेत्र को लेकर रूस पर जो निर्भरता है, उस पर क्या असर पड़ेगा? भारत को कूटनीतिक स्तर पर इसका जवाब तलाशना होगा। असल में, चीन ने हिंद-प्रशांत में अमेरिका की तुलना यूरोप के नैटो एक्सपेंशन से करके यह दिखा दिया है कि वह यहां अपना दबदबा कायम करने की नीति पर आगे बढ़ता रहेगा। इसका अर्थ यह भी है कि जैसे-जैसे अमेरिका हिंद-प्रशांत में आगे बढ़ेगा, चीन उसे टारगेट करेगा। सवाल है कि यूक्रेन में जो हो रहा है, उसका प्रभाव हिंद-प्रशांत में होगा? मुझे लगता है कि यह अपने आप में बड़ा डिवेलपमेंट है और जिस तरह से रूस के साथ चीन खड़ा है, उसे देखते हुए बाकी देशों के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर भारत के लिए। भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं और भारत ने अभी तक यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी नहीं की है। अगर रूस चीन के करीब चला जाता है और रूस पर लगे प्रतिबंधों पर उसे चीन से मदद मिलती है, तो मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। यह भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। हमारा पहले से ही उसके साथ विवाद चल रहा है। हिमालय में हमारी फौजें आमने-सामने खड़ी हैं।

जिस तरह से चीन बार-बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है, वैसी ही स्थिति हिंद-प्रशांत में अमेरिका के आने से बन सकती है, यह एक तरह से धमकी है।

परोक्ष धमकी

हर्ष वी पंत।।

जिस तरह के हालात यूक्रेन में बन रहे हैं, उससे कुछ समय से हिंद-प्रशांत के देश चिंतित हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश हिंद-प्रशांत को लेकर अपनी रणनीति मजबूत कर रहे थे। हो सकता है कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से पश्चिमी देशों का, खासतौर पर अमेरिका का ध्यान बंट जाए। इस इलाके में चीन की जो चुनौती उभरकर आ रही है, उससे सबका ध्यान हटकर रूस की ओर चला जाए। चीन का जो ताजा बयान आया है, उसे देखते हुए यही लगता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह की उथल-पुथल रूस और चीन की दोस्ती से बन रही थी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी।

यूक्रेन क्राइसिस से चीन भले ही थोड़ा परेशान हो, लेकिन एक बार फिर उसने दुनिया का ध्यान इस ओर दिलाया है कि वह हिंद-प्रशांत में अपनी पोजिशन को लेकर नई रणनीति बना रहा है। इसीलिए उसने फिर से यह बात कही है कि जिस तरह से नैटो एक्सपैंशन ने यूरोप में युद्ध के हालात पैदा किए हैं, उसी तरह हिंद-प्रशांत में अमेरिका का आना इस इलाके में और उथल-पुथल बढ़ाएगा। चीन के इस बयान से इस क्षेत्र के अन्य देशों की परेशानी बढ़ेगी क्योंकि चीन की वजह से उन्हें पहले ही दिक्कत हो रही थी। चीन की वजह से इस क्षेत्र में

अस्थिरता के हालात बने हैं और लगता नहीं है कि उसमें कोई कमी आएगी।

चीन ने इस बयान से बाइडन सरकार की उस हिंद-प्रशांत नीति पर निशाना साधा है, जिसे इस साल फरवरी में पेश किया गया था। जिस तरह से चीन बार-बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है, वैसी ही स्थिति हिंद-प्रशांत में अमेरिका के आने से बन सकती है, यह एक तरह से धमकी है। यह धमकी वह अमेरिका और पश्चिमी देशों सहित इस इलाके में मौजूद देशों को दे रहा है। वह उन्हें संदेश दे रहा है कि वे अमेरिका या पश्चिमी देशों के करीब ना जाएं। चीन अपना दबदबा और बढ़ाना चाहता है और हिंद-प्रशांत में अमेरिका का दखल बढ़ने पर उथल-पुथल की बात कहकर वह एक तरह से लकीर खींच रहा है।

पिछले कुछ समय से हिंद-प्रशांत इलाके में नए अलायंस बन रहे थे। कई देशों ने इस क्षेत्र को लेकर अपनी नीति पेश की। इनमें भारत तो शामिल है ही। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, आसियान, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपनी-अपनी नीतियों को सार्वजनिक किया था। इनमें इसी बात पर जोर रहा है कि चीन के आक्रामक रुख से दूसरे देशों की जो परेशानी बढ़ी है, उसे लेकर बाकी देशों के पास क्या उपाय हैं। यह अजेंडा दूसरे देशों के लिए काफी लुभावना है क्योंकि यह सिर्फ चीन को ही टारगेट नहीं करता। इसमें कहा गया है कि हिंद-प्रशांत की जो भी कॉमन समस्याएं हैं, जो सारे देशों को परेशान करती हैं चाहे वे हेल्थ की हों, तकनीक की हों, इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की हों, क्लाइमेट चेंज की हों या रीजनल गवर्नमेंट की हों, उनसे निपटने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे चार बड़े देश किस तरह से योगदान दे सकते हैं। चीन इसी से घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि अगर यह अजेंडा काम कर जाता है तो वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाशिये पर चला जाएगा। इसलिए वह बेचैन है।

सूडोकु नवताल-5319

मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5318 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

अपना ब्लॉग

अपना काम निकाले और दूसरों को धमकाए

मोहन। एक उपाय इस क्षेत्र में समान सोच वाले देशों के साथ आने का था। ये देश चाहते हैं कि हिंद-प्रशांत में कानून का शासन रहे। ये देश नहीं चाहते कि जिसके पास अधिक ताकत है, वह इसके जोर पर अपना काम निकाले और दूसरों को धमकाए। इसी मकसद से पिछले कुछ सालों में ये देश एक साथ आए हैं। इसमें चीन खासतौर पर क्वाड से परेशान है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इन देशों के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर बातचीत चल रही है। उनके बीच सहयोग बढ़ा है। एक समय चीन मान रहा था कि क्वाड कुछ नहीं है। यह कभी बनेगा ही नहीं और बन भी गया तो यह मजबूत अलायंस नहीं होगा। उसकी यह बात गलत निकली। इसे लेकर 2021 में बाइडन सरकार ने खास पहल की। उसने क्वाड में जान डालने का प्रयास किया। बाकी के तीन अन्य सदस्य देशों ने भी इस पर राजनयिक स्तर पर काफी काम किया है। उन्होंने एक अजेंडा भी बनाया है।